स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–8, श्रावण–भाद्रपद 2068, अगस्त 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

बढ़ती महंगाई से बौखलाई सरकार इसे रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है. . . लेकिन पिछले एक साल से यह सभी हदें पार करते हुए आम लोगों का जीवन दूभर बना रही है।

अनुक्रम

आवरण लेख
महंगाई पर सरकार का शुतुरमुर्गी रवैया
– डा. अश्विनी महाजन /4

मंदी
कर्ज के भँवर में अमरीका
– निरंकार सिंह /7

दृष्टिकोण
ताकवर है अपना शेयर बाजार
– आलोक पुराणिक /10

असमानता
असमानता पर उदासनीता
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /12

सामयिकी
खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश
– उमेश चतुर्वेदी /14

अर्थ–तंत्र
क्या हो विकास की सही परिभाषा
– भारत डोगरा /17

पर्यावरण
पर्यावरण के मोर्चे पर शिकस्त
– जगमोहन /20

मुद्दा : देश विरोधी आचरण
– बलवीर पुंज /22

समस्या
सीआईए और मोसाद एजेंसियों के खतरनाक खेल
– ब्रजमोहन जैन /24

आतंकवाद : आतंकियों को अभयदान क्यों?
– अरुण जेटली /26

अंतर्राष्ट्रीय : आतंकवाद से त्रस्त चीन
– वेदप्रताप वैदिक /29

लेख : भारतीय नारी पर पश्चिमी प्रभाव
– रेणु पुराणिक /31

विचार–विमर्श : प्रतिभाएं बनाएंगी आर्थिक महाशक्ति
– जयंतीलाल भंडारी /32

पाठकनामा/2, रपट/34 आंदोलन/35

पाठकनामा

नेता ही भ्रष्ट तो कौन सुने जनता की पुकार

स्वदेशी पत्रिका का हर अंक मैं अपने दोस्त के यहां पढ़ता हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ कि प्रत्येक सरकार का फर्ज बनता है कि वो अपने नागरिकों का ध्यान रखें। परंतु आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद भी आज आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो केवल गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। पिछले 6 सालों से महंगाई इस तरह बढ़ रही है कि वह गरीब आदमी की जान लेने को तुली हुई है।

आज प्रत्येक देशवासी घोटालों से चिंतित है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में इतने घोटाले हुए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में लिप्त पाई गयी। लेकिन क्या कहने कांग्रेस सरकार के जिन्होंने मुख्यमंत्री को माफ कर दिया। यह वही सरकार है जो कहती है कि हर आदमी को काम और हर आदमी को रोटी।

अगर देखा जाए तो आज हर पार्टी में नेता केवल अपना भला चाहते है। उन्हें आम आदमी से कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो बस पैसा चाहिए – पैसा। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के साथ जो कुछ हुआ वो देश की जनता से छिपा नहीं है। एक साधु और दूसरा समाजसेवी जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटने के लिए अपना आंदोलन जारी रखा है लेकिन केन्द्र सरकार है कि उन्हें दिन–प्रति–दिन किसी न किसी मुद्दे में फंसती रहती है। क्या हो गया है आज नेताओं को और क्या हो गया है आज के नागरिकों को, जो बात तो भ्रष्टाचार को मिटाने की करते है लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। मैं स्वदेशी पत्रिका के माध्यम से लोगों को आह्वान करता हूँ कि आज प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य के साथ–साथ धर्म भी बनता है कि वो भ्रष्टाचार को अपने देश से सदैव के लिए मिटे दें।

– महेन्दर मिस्त्री (ठेकेदार) गली नं. 3, सत्य विहार, बुराड़ी, नई दिल्ली

जनता करे कारवाई

आज चीनी ड्रैगन का खूनी पंजा हमारी सरहद पर कब्जा कर रहा है। चीन सामान हमारे बाजार में अपनी पैठ बना चुका है। हर जगह चीनी सामान का बोल–बोला है। इलैक्टॉनिक्स से लेकर हार्डवेयर तक इसने अपनी पैठ बना ली है। तो दूसरी और पाक की आतंकी हरकत दिनोंदिन कश्मीर समस्या को बढ़ावा दे रही हैं वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने समूचा छत्तीसगढ़, बिहार अपने कब्जे में ले रखा है। हमारे नेता हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार करने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो वो इन मुद्दों पर क्यों ध्यान देंगे। अब समय आ गया है कि जनता को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उसे भी लीबिया और यमन जैसी कारवाई करने चाहिए ताकि इन भ्रष्ट नेताओं को गद्दी से उतार कर फैंक देना चाहिए।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

सरकार गोदामों से अनाज मुक्त करे तो खुले बाजार में कीमतें जरूर गिरेंगी। सरकार घाटे की वजह से ऐसा नहीं कर रही है। क्या लोग भूखे मरें और सरकार नुकसान की चिंता करती रहे?

– यशवंत सिन्हा

सरकार के लोकपाल बिल में खोट है। इस लोकपाल बिल की होली देश के गांव–गांव में जलेगी।

– अन्ना हजारे

तेंदुलकर के लंबे समय तक खेलते रहने का रहस्य यही है कि उनके अंदर बच्चों की तरह उत्साह है।

– राहुल द्रविड़

संपादकीय

यह दंगा कुछ कहता है

ब्रिटेन जैसे सभ्य देश में इन दिनों दंगे हो रहे हैं। दंगे के शुरू होने के चाहे जो भी कारण रहे हों, पर एक दिन बाद ही दंगों के स्वरूप जो सामने आए वह पूरी दुनिया की आंखे खोल देने वाले हैं। ब्रिटेन के लोग दंगों में मारपीट कम लूट मार ज्यादा कर रहे हैं। कोई दुकान लूट रहा है, तो कोई किसी से पैसे छिन रहा है। कहीं कोई सिर पर भारी सामान लूट कर भाग रहा है, तो कोई खाने पर ही पिल पड़ रहा है। अचानक इस ब्रिटेन को क्या हो गया? जो आकलन आ रहे हैं, उस पर यकीन करे तो भारत जैसे देशों के लिए खतरे की जबर्दस्त घंटी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में फिर लौट आई भारी मंदी और उसके बाद पूरी दुनिया के शेयर बाजार के लुढ़कने के कारण ब्रिटेन के युवक भयभीत हो गए हैं और खुद भारी घाटा उठाने के बाद आक्रामक भी। उन्हें इस बार मंदी से निकलने का रास्ता कम दिखाई दे रहा है। इसलिए लूट मार में जुट गए हैं। जिसके हाथ जो लग रहा है वही लेकर भाग रहा है। ब्रिटेन के दंगाइयों ने सबसे अधिक रिटेल स्टोरों पर हमले किए। करीज, जेडी स्पोर्ट्स और डेबेनहम्स जैसे बड़े ब्रांड के स्टोर लूट लिए गए। जिस साम्राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था वह साम्राज्य आर्थिक रूप से इतना जर्जर आने लगा है कि उसके खुद के लोग खुद को ही लूटने में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि इस दंगे में कम से कम ब्रिटेन को दस करोड़ पाउंड का नुकसान हो चुका है। लेबर पार्टी के सांसद क्रिस विलियम्सन सीधे ब्रिटेन की सरकार की आर्थिक नीतियों को इस दंगे के लिए जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने सीधे कहा– सरकारी खर्चे में भारी कटौती और करों में वृद्धि ही लोगों में उबाल ला रहा है। यह सच है ब्रिटेन में इन दिनों फिजूल खर्ची को रोकने के नाम पर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए हो रहे खर्चों पर भी कटौती कर दी है। बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। यह अकेले ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के फेल होने का परिणाम नहीं है, बल्कि ब्रिटेन पर अमरीका और यूरोप के अन्य देशों में छायी मंदी का ज्यादा असर है। 'दि टेलीग्राफ' लिखता है। वैश्विक मंदी ने फिर से सबको सड़क पर ला खड़ा किया है। अब जिसको जो मन मे आता है वह कर रहा है। युवा वर्ग सबसे ज्यादा उखड़ा हुआ है। यूरोप या अमरीका अब अपने ही किए की भरपाई कर रहा है। उनकी आर्थिक नीतियों ने समाज के सबसे बड़े वर्ग को गरीब से ज्यादा गरीब बना दिया है। 'दि गार्जियन' में नीना पवर लिखती हैं– गरीबी, बेरोजगारी और उस पर पुलिस की ज्यादती तो दंगे के लिए जिम्मेदार है ही, उससे कहीं अधिक जिम्मेदार वे आर्थिक नीतियां है जिनसे 'अमीर और अमीर' 'गरीब और गरीब' होते जा रहे हैं। ब्रिटेन के दस फीसदी लोगों के पास गरीबों के मुकाबले 100 गुनी अधिक सुख सुविधा की चीजें हैं। ब्रिटेन की सामाजिक स्थिति अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा खराब है। खासकर पिछले छह महीने में ब्रिटेन की माली हालात ज्यादा खराब हुई है। विकास दर लगभग नकारात्मक है। आकलन यह है कि इस साल आर्थिक विकास दर 1.1 फीसदी रहने वाली है। ऐसा अकेले ब्रिटेन में नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में है। साख संकट अमरीका से भी पहले यूरोप में ही पहुंचा। जेपी मार्गन ने यह आशंका जताई है कि अमरीका और ब्रिटेन में लगभग हर तीसरे साल मंदी का खतरा है। अभी से ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसिया अमरीका की तरह यूरोप को भी निवेश के लिए जोखिम वाले देशों में शामिल करने की तैयारी कर रही हैं। एक बड़े निवेशक का कहना है कि यह असंभव है कि अमरीका की रेटिंग घटाने के बाद ब्रिटेन समेत यूरोप की अन्य अर्थव्यवस्था की रेटिंग न घटे। साख संकट से बचने के लिए ब्रिटने के पास अन्य उपायों के साथ एक और महत्वपूर्ण उपाय यह बचता है कि वह अधिक से अधिक मुद्रा की प्रिंटिंग करे और उसका खतरा यह है कि पाउंड की कीमत कम होगी और महंगाई और बढ़ेगी। आईएमएफ ने भी चेताया है कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन की हालत और खराब हो सकती है, क्योंकि अन्य यूरोपीय देषों में छाये साख संकट से ब्रिटेन के बैंक भी बुरी तरह प्रभावित हैं। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार में मुर्दनी छायी हुई है। आईएमएफ का आकलन है कि इस साल ब्रिटेन की आर्थिक विकास दर दो फीसदी से नीचे ही रहेगी। डरने की जरूरत सिर्फ ब्रिटेन और अमरीका की सरकारों को ही नहीं है। कहीं न कहीं खतरा हमारे ऊपर भी आने वाला है। खास कर हमारे निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। अमरीकी डॉलर और ब्रिटेन के पाउंड की कीमत घटने के साथ ही हमारे निर्यातकों के भी रक्तचाप घट बढ़ रहे हैं। अब यह समय है कि अरीमका और ब्रिटेन की हालात से सबक ले और कर्ज के आधार पर बुनी अर्थव्यवस्था की अर्थनीति को विदा कर बचत आधारित अर्थव्यवस्था को लागू करे। हम आज तक बचे ही इसलिए है कि हमारी जनता आज भी बचत को सर्वाधिक महत्व देती है। नहीं हो उपभोगवादी संस्कृति का जिस तरह पालन किया गया है, वह हमें डुबोने के लिए काफी है। हालांकि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी यह दम भरते हैं कि अमरीका और यूरोप में आए संकट का भारत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर इस आशंका को वह भी खारिज नहीं करते कि यदि उनका आर्थिक संकट लंबा चला तो भारत को कुछ ठोस और त्वरित कदम उठाने पड़ेंगे। हाल के दिनों में रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति इसी बात की ओर संकेत करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए महंगाई को निमंत्रण दिया जा रहा है। हर प्रकार के कर्ज को महंगा किया गया है। ताकि मांग में कमी आए। पर इसका असर उल्टा भी हो सकता है। आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। उद्योग धंधे पर खतरा मंडरा सकता है और विकास दर भी प्रभावित हो सकता है।

महंगाई पर सरकार का शुतुरमुर्गी रवैया

बढ़ती महंगाई से बौखलाई सरकार इसे रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है। यों तो पिछले तीन सालों से महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन पिछले एक साल से यह सभी हदें पार करते हुए आम लोगों का जीवन दूभर बना रही है। महंगाई में सर्वाधिक चोट अति गरीब आदमी पर पड़ रही है, क्योंकि उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ मसलन अनाज, दालें, खाद्य तेल और फल–सब्जियां विशेषतौर पर महंगे हुए हैं।

■ डा. अश्विनी महाजन

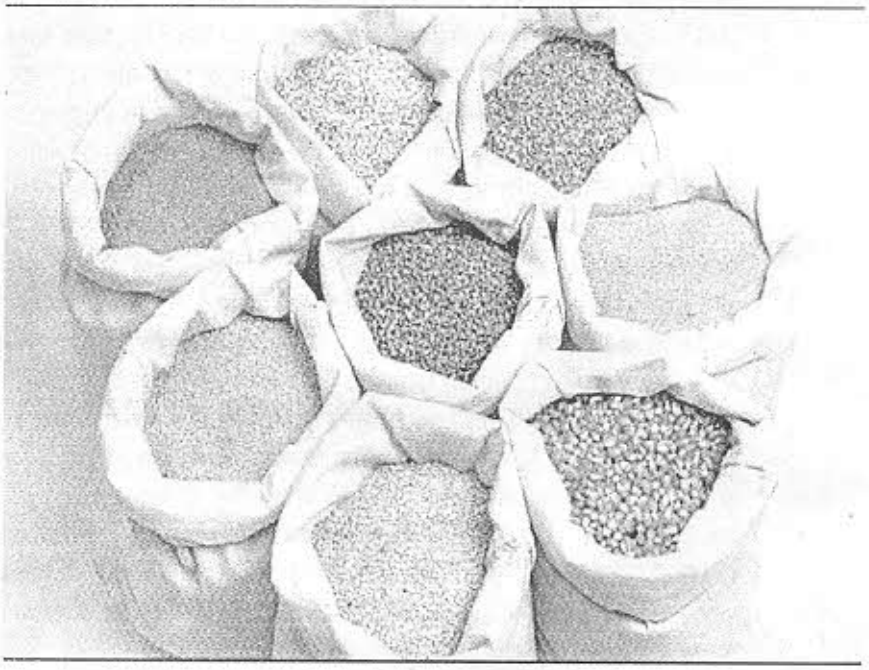

बढ़ती महंगाई से बौखलाई सरकार इसे रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है। यों तो पिछले तीन सालों से महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन पिछले एक साल से यह सभी हदें पार करते हुए आम लोगों का जीवन दूभर बना रही है।

इस महंगाई में सर्वाधिक चोट अति गरीब आदमी पर पड़ रही है, क्योंकि उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ मसलन अनाज, दालें, खाद्य तेल और फल–सब्जियां विशेषतौर पर महंगे हुए हैं।

महंगाई के सामने लाचार सरकार हर बार रिजर्व बैंक का द्वार ठोंकते हुए उसे ही बाध्य कर रही है कि वह येन–केन–प्रकारेण महंगाई को काबू करने का प्रयास करे। इस कवायद में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट में .5 बेसिस प्वाइंट यानी आधा फीसदी की वृद्धि करते हुए उन्हें क्रमशः आठ और सात प्रतिशत कर दिया है।

रेपोरेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपोरेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। ब्याज दरों में यह वृद्धि 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में तीसरी वृद्धि है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आठ बार वृद्धि की थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मात्र 16 महीनों में 11 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी सीधे तौर पर संकुचनवादी मौद्रिक नीति मानी जा सकती है।

सामान्य तौर पर माना जाता है कि महंगाई का प्रमुख कारण मांग में वृद्धि होता है। वस्तुओं की कम उपलब्धता और बढ़ती मांग कीमतों पर दबाव बनाती है, इसलिए रिजर्व बैंक परंपरागत तौर पर ब्याज दरों में वृद्धि कर कीमतों को शांत करने का प्रयास करता है।

लेकिन विडंबना यह है कि इतने कम समय में ब्याज दरों में भारी वृद्धि के बावजूद कीमत वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रही और जुलाई माह तक आते–आते पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई 9.5 प्रतिशत बढ़ गई। खाद्य पदार्थों में यह वृद्धि 12.3 प्रतिशत की थी, लेकिन रिजर्व बैंक की मृग–मरीचिका का कोई अंत नहीं है।

ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और अधिक वृद्धि भी कर सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि के खतरे आज बढ़ती आमदनी के युग में मध्यम वर्ग, विशेष तौर पर मध्यवर्गीय युवा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जुगत में रहता है। ऐसे में अच्छा और अपना घर, कार या मोटर साइकिल और जीवन के

अन्य साजो–समान खरीदने के लिए वह बैंकों से उधार लेता है और उसे किश्तों यानी ईएमआइ से चुकाता है।

पश्चिमी देशों से आई इस पद्धति से जीवन स्तर तो बेहतर हुआ, लेकिन आम आदमी की देनदारियां भी बढ़ गई हैं। यह देनदारियां सामान्यतः स्थिर ब्याज दर पर आधारित नहीं होतीं। बढ़ते ब्याज दर से ईएमआई भी बढ़ जाती है। ऐसे में मध्यम वर्ग की ईएमआई बढ़ते जाने से रोजमर्रा के लिए उसके पास आमदनी बहुत कम बचती है।

ब्याज दरों का पेच यदि पिछले दस वर्षों का हिसाब देखें तो पाते हैं कि कृषि की विकास दर कम होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में आमदनियां बढ़ीं और अर्थव्यवस्था की सकल संवृद्धि दर 8 से 9 प्रतिशत के बीच रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस दशक के पहले 6–7 वर्षों तक कीमतों में वृद्धि को काफी हद तक काबू में रखा जा सका। कीमतों में अपेक्षित नियंत्रण के चलते ब्याज दरें घटने लगीं। हालांकि घटती ब्याज दरों ने एक ऐसे वर्ग, जो ब्याज की आय पर आधारित था, को प्रभावित तो किया, लेकिन घटती ब्याज दरों ने देश में घरों, कारों, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं आदि की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि की। कम ब्याज दरों के चलते सरकार द्वारा अपने पूर्व में लिए गए ऋणों की ब्याज अदायगी पर भी अनुकूल असर पड़ा।

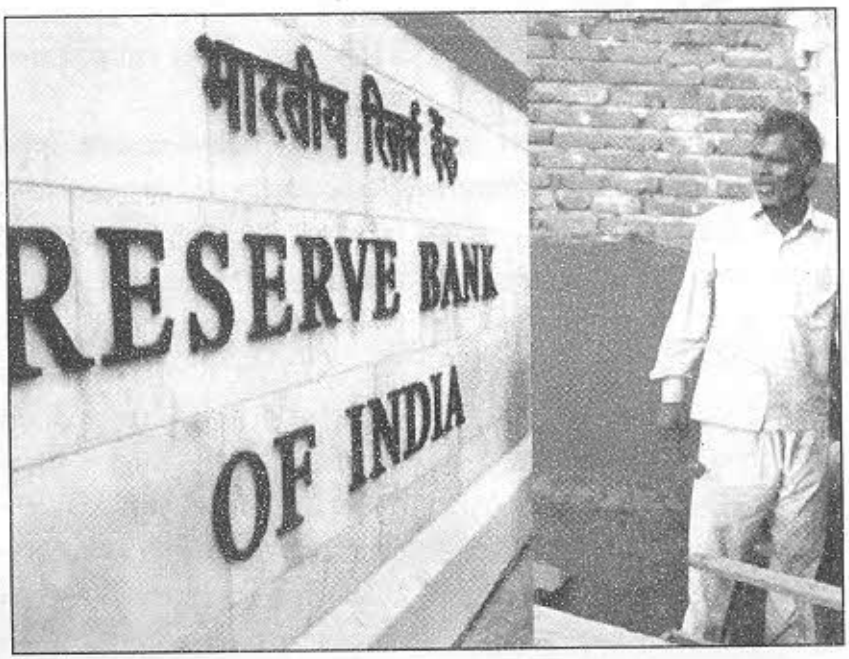

हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास होना शुरू हुआ और देश–दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया।

वर्तमान में देश में महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत। खाद्य पदार्थों की महंगाई बाजार में तरलता अधिक होने के कारण नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण है। इसलिए खाद्य मुद्रा स्फीति को काबू में रखने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, न कि ब्याज दरों को।

कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक संवृद्धि की गाथा में ब्याज दरों के घटने की एक प्रमुख भूमिका रही है। विकास की ऊंची दर के लिए जरूरी है कि ब्याज दरों को नीचा रखा जाए, लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में यह बात मुश्किल हो जाती है।

एक ओर तो रिजर्व बैंक को महंगाई पर काबू करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ती है तो दूसरी ओर ब्याज अर्जित करने वाले वर्ग को बचत करने और उसे बैंकों के पास जमा करने हेतु प्रेरित करने के लिए ब्याज दर को महंगाई की दर से ऊंचा रखना पड़ता है। इसलिए देश में आर्थिक संवृद्धि की दर को तेज करने के लिए ब्याज दरों को घटाना जरूरी है और ब्याज दरों को घटाने के लिए महंगाई पर काबू पाना जरूरी है। बढ़ेगा ब्याज तो रुकेगी महंगाई?

पिछले कुछ समय का अनुभव यह बताता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि नहीं रुक रही। वर्तमान में देश में महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत। खाद्य पदार्थों की महंगाई बाजार में तरलता अधिक होने के कारण नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण है।

इसलिए खाद्य मुद्रा स्फीति को काबू में रखने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, न कि ब्याज दरों को।

पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को बाजार पर छोड़ दिए जाने के कारण, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो महंगाई का मुख्य सबब बन रही है। ब्याज दरों को बढ़ाने से महंगाई के इस कारण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए महंगाई के कारणों की जांच करते हुए उस पर प्रभावी नियंत्रण देश को आर्थिक संवृद्धि और विकास की पटरी पर रखने के लिए बहुत जरूरी है। मांग में कमी या आपूर्ति में वृद्धि! ब्याज दर बढ़ाकर या बैंकों के रिजर्व बढ़ाकर रिजर्व बैंक यह कोशिश कर सकता है कि महंगाई की दर घट जाए।

जब रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो उधार की लागत बढ़ जाती है, जिससे लोग कम उधार लेते हैं। ऐसे में कारों, घरों और अन्य साजो–समान की मांग घटने से उनका उत्पादन भी घट जाता है। इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि को धक्का पहुंचता है।

हालांकि अभी तक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद ऑटोमोबाइल आदि की मांग में कोई विशेष कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन तमाम रियायतों के बावजूद गृह निर्माण क्षेत्र में मंदी साफ दिखाई देती है। फिर भी इन सब के बावजूद कीमतें थम नहीं रहीं। लेकिन अगर सरकार पूर्ति पक्ष की तरफ ध्यान दे तो कीमतों में वृद्धि भी थम सकती है और ब्याज दरों को भी सीमा में रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार कृषि विकास की ओर उचित ध्यान दे।

पिछले लगभग दो दशकों से चल रही कृषि की अनदेखी ने कृषि विकास को बाधित किया है। खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों और फल–सब्जियों का उत्पादन थम गया है। बढ़ती आमदनियों के चलते खाद्य पदार्थों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन पूर्ति नहीं। ऐसे में पिछले लगभग पांच वर्षों में खाद्य पदार्थों की महंगाई की दर अन्य पदार्थों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक रही है। ऐसे में नीति निर्माता कृषि की अनदेखी समाप्त कर किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई, उर्वरक और अच्छे बीजों की व्यवस्था समेत सभी प्रोत्साहन प्रदान करें, तभी महंगाई का इलाज हो सकता है।

रिजर्व बैंक के बार–बार ब्याज दरों को बढ़ाने की कार्रवाई ने अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। इसके कारण सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए आर्थिक संवृद्धि की अपेक्षित दर भी 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस वर्ष आर्थिक संवृद्धि की दर इससे भी कम हो सकती है। हर बार रिजर्व बैंक को ही महंगाई रोकने का जिम्मा देना न केवल अर्थव्यवस्था में मंदी लाएगा, बल्कि भविष्य में महंगाई को रोकने के प्रयासों की कारगरता पर भी असर पड़ेगा। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022